मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

वर्ष 58 | फरवरी, 2013 | अंक 2

सभापति का पत्र :

'हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन'

जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमें एक गाना सुनाया जाता था, 'हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन'। सफलता का वह दिन बहुमत में किसानों के लिए अभी तक नहीं आया है, उन्नीस सौ अस्सी या नब्बे के दशक के शुरू में जो उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, वह अब तेजी से लुप्त हो रही है। असंतुलित विकास की नीतियों के परिणामस्वरूप लगभग सभी किसान अपने बच्चों से खेती नहीं करवाना चाहते और न ही अपनी बेटियों की शादी किसानों से करना चाहते। केवल एक ही कारण है जिसकी वजह से किसान अभी भी खेती कर रहे हैं और वह है सुलभ विकल्पों का अभाव। 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के अंतर्गत युवाओं को कृषि में बनाए रखने का आज कोई अस्तित्व नहीं है। जिस तरह से कृषि आज एक व्यवसाय के रूप में तैनात है, उस तरह कोई भी युवा कृषि में नहीं बने रहना चाहता। खेतों पर से लोगों को कम करक खेतों पर जनसंख्या के बढ़ते दबाव को कम करने की शीघ्र आवश्यकता है। लेकिन जो सरकार या कॉर्पोरेट सैक्टर में नीति बनाते हैं या उसे प्रभावित करते हैं वह फैसला कर रहे हैं कि कैसे दूसरों को जीना चाहिए या दुर्भाग्य से जीने की उम्मीद कर रहे हैं। केवल अब एक ही उपाय सामने आ रहा है, और वह है खेती को लाभदायक व्यवसाय बनाना।

आधे से ज्यादा भारत सीधे तौर पर कृषि में कार्यरत है। अब एक बार सोचिऐ कि विभिन्न राज्यों में मुख्य मंत्रियों या मंत्रियों में से कितने वास्तव में कृषि पर एक व्यवसाय के तौर पर निर्भर हैं या उन्होंने वास्तव में कभी खेतों पर काम किया है। इस सवाल का जवाब हम से में सबसे आशावादी को एक नई जागृति का एहसास कराऐगा। यह समझा जाऐगा कि धन के वितरण का अनुवाद उन लोगों की इच्छा पर निर्भर करता है जो कि राज करते हैं। इसमें नितियों की अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डलेगा जो कि मुख्य धारा से हटकर अलग–थलग पड़ रही हैं।

साक्षात्कार के दौरान (इस अंक में छपा है) डॉ० अय्यपन ने कबूल किया कि

आईसीएआर के लिए आबंटित धन को कम कर दिया गया है। अच्छी सर्दियों से खाद्य उत्पादन में वृद्धि होगी और यह अच्छा भी है, उम्मीद है कि सरकार गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करेगी। एक छोटा किसान एक चपरासी के बराबर कमाऐ इसके लिऐ गेहूँ के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा जो कि कभी नहीं होगा। प्राथमिकता में इस तरह का अभाव एक चिंता का विषय है।

कृषि देश में सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की गतिविधि है और अधिकांश के लिऐ लाभहीन है। कृषि क्षेत्र में असली मुद्दों की समझ के सवर्थ अभाव के कारण भारतीय कृषि में संकट बढ़ता जा रहा है। सरकार गहन सार्वजनिक जांच के दायरे में अपने तरीके को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन केवल अधिक से अधिक नीतियों की घोषणा तथा उनकी सुधारों के रूप में दलाल के बजाऐ और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

अजय वीर जाखड़ द्वारा डॉ० एस. अय्यापन, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) का साक्षात्कार

प्रश्न – महोदय, आईसीएआर एक बहुत बड़ी संस्था है। भारत में कृषि अनुसंधान की यह प्रमुख संस्था है। इसमें कितने कर्मचारी हैं और आईसीएआर का कितना बजट है ?

उत्तर – लगभग 6,000 वैज्ञानिक हैं। यह अनुसंधान की प्रमुख क्षमता है जिसके सहयोग के लिए 7,000 तकनीकी सहायक, लगभग 5,000 प्रशासनिक कर्मचारी और लगभग 7,000 सहायक स्टॉफ हैं। चालू वित्तीय वर्ष का बजट 3,200 करोड़ रू. था किन्तु इसमें कुछ संशोधन हो रहे हैं। इस कारण यह कम हो सकता है।

प्रश्न – निर्धारित व्यय से थोड़ा सा कम.....

उत्तर – हाँ, इसमें कमी की जाएगी।

प्रश्न – इस प्रकार कृषि मंत्रालय के बीच, आईसीएआर और राज्य सरकारों तथा विभिन्न संस्थाओं के बीच समन्वय की समस्या है ?

उत्तर – वास्तव में हम तकनीकी प्रचार जिस प्रकार कर रहे हैं यह क्या हैं..... हम डीएसई की अन्तर बैठकों में जाते हैं और दो वर्ष में एक बार..... खरीफ और रबी मौसम से पहले। इस प्रकार सभी एपीसीज़ और कृषि के, पशुपालन के निदेशक सभी दो दिन के लिए वहाँ होते हैं। हम अपनी तकनीक की प्रस्तुति करते हैं और सम्भावनाओं का पता लगाते हैं। दूसरा है प्रस्तुति या प्रदर्शन। दो अन्य पद्धतियाँ भी हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों में हम नई तकनीक और किस्मों को प्रदर्शन करते हैं। दूसरा है अनुसंधान परियोजना ट्रायलस का अखिल भारतीय समन्वय। वे भी राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में पर्याप्त हैं।

राज्य कृषि विश्वविद्यालय आईसीएआर के द्वारा प्रशासित नहीं होते किन्तु हमारे द्वारा उनका समन्वय किया जाता। अतः वहाँ अनुसंधान कार्यक्रम और विस्तार..... राज्य कृषि विद्यालयों की विस्तार मशीनरी को कृषि विज्ञान केन्द्रों के अनुरूप बनाया जाता। तब राज्य विभागों से वार्तालाप की जाती है और उनके द्वारा पूछे गए विशेष प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है, कई बार इनका प्रदर्शन करके, जैसा मैंने कहा प्रशिक्षण कार्यक्रम।

प्रश्न – तो क्या वहाँ कोई समस्या नहीं ?

उत्तर – नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, हमारे देश में समस्याएँ तो होंगी। किन्तु राज्य सरकारों, राज्य विभागों के साथ वार्तालाप करने के लिए एक अन्य प्रमुख मैकेनिज़्म है कि क्षेत्रीय समिति की बैठकें की जाती हैं, आईसीएआर क्षेत्रीय समिति की बैठकें की जाती हैं। ये क्षेत्रीय समितियाँ, इनमें से 8, दो वर्ष में एक बार बैठक करती है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय समिति की तिमाही बैठकें होती हैं।

प्रश्न – आप अपने काम की समीक्षा करते हैं और नए विचार प्रकट करते हैं.....

उत्तर – वे अपने मुद्दे प्रस्तुत करते हैं और हम उन्हें अनुसंधान कार्यसूची में शामिल करते हैं तथा हम रिकॉर्ड करते हैं कि हमने कितना प्राप्त किया और कितना प्राप्त नहीं कर पाए।

प्रश्न – क्या आप अगली 5 वर्षीय योजना के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में आईसीएआर की सिफारिशों से संतुष्ट हैं ?

उत्तर – हमारे संचालन समूह.... आईसीएआर पिछले डेढ़ वर्ष की सिफारिशें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 55,000 करोड़ रू. की थी। किन्तु अभी भी हमारे पास अंतिम आंकड़ें नहीं हैं। बैठक शीघ्र होनी है।

प्रश्न – हम अच्छे की आशा करते हैं। हमें कई गैर सरकारी संस्थाओं, समाचार–पत्रों और मीडिया से जैविक पद्धतियों के बारे में माँगे आ रही हैं। क्या आईसीएआर जैविक पद्धतियों के प्रचार के लिए कुछ कर रहा है।

उत्तर – हमारे पास जैव कीटनाशक, जैव उर्वरकों पर विशेष परियोजनाएँ हैं और विभिन्न जिन्सों के जैविक कृषि से संबंधित एक परियोजना भी है। अतः हमें यह कहना है कि जैविक पद्धति अच्छी है, बेहतर मूल्य देती है जहाँ सम्भव होता है, हालांकि प्रत्येक वस्तु के लिए नहीं। इस देश की मिट्टी में जैविक कार्बन 0.34 प्रतिशत हैं। इस प्रकार कई स्थानों पर जैविक कृषि उपयोगी है और अच्छा लाभ देती है। किन्तु व्यापक सिफारिशों में कहा गया है कि जैविक कृषि उस प्रत्येक स्थान पर अपनाई जाए जहाँ पर मिट्टी की स्थिति अच्छी हो। इस प्रकार हम समेकित न्यूट्रीऐंट प्रबंधन की बात कर रहे हैं। संतुलित उर्वरकों, नाईट्रोजन का उपयोग ठीक है किन्तु पौटेशियम और फॉसफोरस के लिए यह कहना है कि जब तक इसके स्थान पर दूसरा कुछ उपयोग नहीं

करते तब तक यह समस्या है। विभिन्न प्रकार के जैविक खादों के मामले में जैविक कार्बन पर्याप्त होता है, कुछ मात्रा माईक्रोन्यूट्रीयनस की होती है। किन्तु ये सभी संतुलित मात्रा में होते हैं। कृषि में पशु और पशुधन की कमी भी एक समस्या बनती जा रही है। पहले पशुओं को कृषि में उपयोग किया जाता था। कुछ राज्यों में अभी भी प्रयोग किया जाता है जैसे मध्य भारत में, वहाँ पर सब ठीक है। अन्य स्थानों पर जैसे उदाहरण के लिए हरित कांति क्षेत्रों में जहाँ पर लगभग मशीनों और गैर जैविक खादों का उपयोग किया जाता है वहाँ पर जैविक कृषि एक समस्या होगी।

प्रश्न – महोदय, पशुपालन एक समस्या है क्योंकि जब आप छोटे और मझोलें किसानों की बात करते हैं तो पशुपालन परिवार के पालन पोषण के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। पिछले बहुत से वर्षों से फसल विज्ञान पर ध्यान केन्द्रित है। अतः क्या आईसीएआर अब पशुपालन और मच्छलीपालन पर ध्यान दे रहा है ?

उत्तर – हम इसकी प्रशंसा करते हैं। पशुपालन और इससे संबंधित डेरी, कुक्कट पालन, मच्छलीपालन का योगदान कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत से अधिक है। अतः इसकी प्रशंसा की जाती है और हम देश में इसे ला रहे हैं क्योंकि इस देश में कोई एक प्रकार के कार्य उपयोगी नहीं है। प्रत्येक कार्य फसल और पशु आधारित होती है। अतः समेकित कृषि पद्धति को बढ़ाना होगा। अभी हमारे पास लगभग पूरे देश में समेकित कृषि पद्धति के 300 विभिन्न मॉडल हैं और इस योजना में पशुधन, अनुसंधान और संबंधित गतिविधियों पर अधिक बल दिया जा रहा है।

प्रश्न – जीएम फसलें एक बहुत विवादास्पद विषय है। क्या आईसीएआर के लिए यह सम्भव है कि देशी तकनीक अपनाई जाए ताकि हम तकनीक के लिए अन्य पर निर्भर न रहें ? आप सोचते हैं कि भावी दिनों में हमारे पास अपनी तकनीक होगी क्योंकि जीएम के लिए बहुत विवाद उत्पन्न हुआ क्योंकि यह विदेशी कम्पनियों और विदेशों से था। तो क्या आप सोचते हैं कि आईसीएआर और भारतीय कम्पनियाँ इन तकनीकों को अपना पाएँगी।

उत्तर – जीएम फसलों में हमने जागरूकता अभियान चलाया है। सामान्य रूप से बायोटैक और विशेषरूप से जीएम फसलों में। तिमाही आधार पर समाचार पत्र प्रकाशित किए जाते हैं ताकि जिला स्तर पर लोग जागरूक हो सकें। वास्तव में हम देशी भाषा की प्रैस से वार्ता करते हैं क्योंकि इनमें से बहुत से वैब साईट और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया से कहानियाँ उठाते हैं। हम उन्हें सामग्री, जीएम फसलों का सार आदि देने की कोशिश करते हैं। दूसरा बिन्दू इस क्षेत्र में हमारे निवेश से संबंधित है किन्तु यह उच्च स्तर तक नहीं पहुँचता है जैसे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में होता है। अतः यह एक धारणा है कि यह केवल उनका उत्पाद है किन्तु मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे अधिक कुछ और भी है। यह सदा वृद्धि के लिए ही नहीं होता। शाकनाशी,

सहनता, सूखे से निपटने की स्थिति जानने के लिए इनमें से कई उत्पाद बिक्री के लिए तैयार हैं लगभग एक दर्जन। अभी चाहे जो कुछ भी है हम इन एजेंसियों को सभी सामग्री दे चुके हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय भी शामिल है। हमें विश्वास है कि विद्यमान मशीनरी से सह विनियम प्राधिकरण को और उत्पाद प्राप्त होंगे जिसके लिए देशी निवेश करना होगा और थोड़ा और ध्यान देना होगा जिससे हम मल्टी मिनिस्ट्रीयल, एक मल्टी डिपार्टमेंटल प्रदान करने का प्रयास करेंगे।

प्रश्न – महोदय, आईसीएआर का प्रमुख होने के नाते क्या आप समझते हैं कि भारतीय वैज्ञानिक प्रगति कर सकते हैं यदि उन्हें निजी क्षेत्र, बाहर के गैर सरकारी संस्थाओं के साथ दो वर्ष का या तीन वर्ष का कार्य करने का मौका मिले, इससे वे वापिस लौटेंगे और वाणिज्यिक रूप में अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे..... आप उस ज्ञान की बिक्री कर सकते हैं जो आपके पास है ?

उत्तर – कोई भी प्रदर्शन या प्रस्तुति अच्छी होती है। अतः सबसे पहले हमने विदेशों में अच्छी प्रयोगशालाएँ देखी। अतः हमने वहाँ पर 5 वर्ष के लिए 700 लोगों को भेजा जो राष्ट्रीय कृषि पद्धति से कार्य कर रहे थे। अतः किसी प्रकार का भी प्रशिक्षण अच्छा होगा। किन्तु पिछले दो वर्षों से हम सार्वजनिक और निजी प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और पद्धति का आदान प्रदान कर रहे हैं। इस प्रकार वे निजी पद्धति में जिस प्रकार कार्य करते हैं..... बहुत अनुसंधान केन्द्रित होता है और तेजी से प्रशिक्षण चलता है न कि एनएएएस की तरह जहाँ पर हमें अन्य कई मुद्दों से निपटना पड़ता है।

अतः हम प्रशंसा करते हैं और बैठकों के तिमाही आयोजन के लिए कई कम्पनियों को आमंत्रित करते हैं। विशेष सुझाव यह है कि हमारे दर्जनों साथी अपने–अपने स्थानों पर कार्य करते हैं जैसा पिछले सप्ताह में हमने महाराष्ट्र में देखा। अतः हमने कई बीज कम्पनियों को यह प्रस्ताव दिया है। देखते हैं कि क्या होता है। हमारे पास ग्रीन इनोवेट इण्डिया कम्पनी भी है। अतः हमने उनकी ओर से कई लोगों को आमंत्रित किया है कि वे बीज, कृषि उपकरणों, मशीनरीज़, पहचान टीको, मूल्य बढ़ाने वाले उत्पादों के संबंध में हमारे साथ काम करें।

प्रश्न – महोदय, मैं आपका कुछ समय ओर लूँगा। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से आपने आईसीएआर की बैठक में एक अच्छी बात कही कि पीपीपी, आपका पीपीपी से कार्य करने का ढंग अन्य पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप से भिन्न था। अतः आप पाठकों के लिए इस पर विवरण प्रस्तुत करें ?

उत्तर – जैसा मैंने आपसे कहा कुछ नहीं..... कृषि में लाभ। सभी मानते हैं कि यह गैर लाभकारी है, यह रूचिकर नहीं है, यह एक बुद्धिपूर्ण व्यापार नहीं है और यह कार्य तो चलता ही रहता है। सबसे पहले मैं कहूँगा कि कृषि एक कुशल कारोबार है और हम किसानों से पूछते रहते हैं – उनका कहना है कि एक सफल किसान होने के लिए कम

से कम 50 कुशलताएँ होनी चाहिऐं। अतः हम उनका प्रदर्शन करना चाहेंगे और कहते हैं कि सबसे पहले लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा कृषि में प्रतिष्ठा है। क्यों नहीं ? यह अंतिम विकल्पों में से नहीं है। यह दूसरा है। तीसरा निस्संदेह समृद्धता है।

प्रश्न – दूसरी बात है कि छोटे स्तर की खेती लाभकारी नहीं है और आईसीएआर भूमि सीमा में कमी का समर्थन करेगा और कृप्या भूमि मुद्दों पर अपने विचार दें ?

उत्तर – सबसे पहले हम सिंचाई से दूर हो रही भूमि के लिए चिंतित हैं। नागपुर स्थित संस्था का विश्वास है कि यह खतरनाक नहीं है.... आप देख रहे हैं कि बड़े–बड़े हरे खेतों पर मकान बन गए हैं। उन्होंने कहा है कि वे इसकी निगरानी कर रहे हैं और जब थोड़ी भूमि भी जाती है तो कृषि भूमि के स्थान पर कुछ जंगलों की भूमि पर सिंचाई की जाने लगती है। इस प्रकार लगभग 140–142 मिलियन हैक्टेयर भूमि स्थिर ही रहती है। दूसरा भूमि रखने के संबंध में है, सामाजिक परिदृश्य को देखते हुए हमारे लिए इस पर प्रकाश डालना बहुत कठिन है। हम हर प्रकार से संतुलन का प्रयास कर रहे हैं। कस्टोमाईज़ करने का अर्थ है कृषि उपकरणों, मशीनरी को छोटे–छोटे किसानों के लिए कस्टोमाईज़ करना। इस देश में ही छोटे–छोटे टुकड़ों पर खेती नहीं होती है बल्कि कई देशों में यह समस्या है तो कस्टोमाईज़ का क्या अर्थ हुआ ? सर्वप्रथम सिंचाई। क्या यह सामूहिक खेती हो सकती है ? क्या यह मिश्रित सिंचाई हो सकती है ? हमने इसका प्रदर्शन आंध्रप्रदेश के कुछ स्थानों पर किया जहाँ पर उनके अपने कुँए नहीं थे, वहाँ पर सामूहिक सिंचाई की संभावना है। अतः सर्वप्रथम सामूहिक खेती है। दूसरा उपयोग की जाने वाली खेती की मशीनरी कस्टोमाईज़ है। तीसरा मिलकर बाज़ार जाना है। मैं सहकारी संस्था नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा यदि आप 200 लागे एक ही कार्य कर रहे हैं तो इक्कट्ठे हो जाओ। एक सामान्य उपकरण प्रबन्धन रखें जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मशीनरी आदि सभी का सामूहिक उपयोग हो। एक सामान्य फसल कटाई की रणनीति और बाज़ार रखें। यह रणनीति सफल हो रही है और हम कुछ और मॉडलों की स्थापना भी करने जा रहे हैं।

प्रश्न – कृषि विज्ञान केन्द्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब आप इनका भ्रमण करते हैं तो आप पाते हैं कि यहाँ प्रस्ताव की बहुत कमी है जैसी अनुसंधान नेटवर्क में है। कई स्थानों पर रिक्तियाँ हैं किन्तु उन्हें भरा नहीं गया है। क्या वह संसाधनों की कमी है या उन्हें किराए पर लेने की समस्या है ?

उत्तर – अपनी ओर से मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि विज्ञान केन्द्र 100 प्रतिशत आईसीएआर द्वारा संचालित पद्धति है यह एक योजनाबद्ध परियोजना है। 100 प्रतिशत केन्द्र की ओर से है। आज हमारे पास 630 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं। 6 पदों पर विशेषज्ञ हैं, एक कार्यक्रम समन्वयक और कुल स्टॉफ 60 का है। हमारी ओर से पर्याप्त निधियाँ उपलब्ध हैं। अब लगभग 400 कृषि विज्ञान केन्द्र विश्वविद्यालयों के पास हैं। इनमें से

100 गैर सरकारी संस्थाओं के साथ और 100 आईसीएआर की संस्थाओं के साथ हैं। अब निधियों की समस्या नहीं है किन्तु भर्ती प्रकिया की समस्या है। यह स्थान जिला स्तर पर और कभी–कभी दूर के क्षेत्रों में स्थित है। अतः भर्ती एजेंसी.... लोग आते हैं और बताते हैं कि उन्हें स्टॉफ नहीं मिल रहा है किन्तु हम पूरी भर्ती सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक बहु अनुशासनिक प्रकिया है पर हमारी एक मानक पद्धति निर्धारित है और कृषि विज्ञान को भूमि संरक्षण व्यक्ति, सामान्य रूप में पशु विशेषज्ञ आदि की आवश्यकता है। हम इस कमी को भी पूरा कर रहे हैं जो विभिन्न स्थानों की आवश्यकता पर निर्भर करता है। वे इन क्षेत्रों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। यह सब लचीला क्षेत्र है। यह स्थान पर निर्भर करता है कि अधिक महत्वपूर्ण क्या है। समुद्री क्षेत्रों में मछलीपालन महत्वपूर्ण हो सकता है। गुजरात में डेरी महत्वपूर्ण है। निधियाँ और लचीलापन होने के कारण हमारा प्रयास है कि इन सबको भरा जाए हम सभी पदों को भरने का भी प्रयास कर रहे हैं क्योंकि माध्यमिक कृषि महत्वपूर्ण है, मशीनीकरण और जलवायु परिवर्तन महत्वपूर्ण हो रहा है। इस प्रकार हम समझते हैं कि ये तीन लोग, कृषि जलवायु वैज्ञानिक, यदि सम्भव हो तो वहाँ इंजीनियर और ऐसे व्यक्ति जो विपणन कुशलता में निपुण हो जिन्हें कारोबार का ज्ञान हो उन्हें वहाँ होना चाहिए।

प्रश्न – महोदय दो प्रश्न और हैं। एनसीएपी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित संस्था के रूप में उभरा है। किन्तु आंकड़े एकत्रित करने के संबंध में क्या है ? क्या आप समझते हैं कि आंकड़े संग्रह के लिए और आवश्यकता है क्योंकि बहुत सी नीतियाँ संग्रह किए गए आंकड़ों पर आधारित होती हैं। अतः क्या आप समझते हैं कि आंकड़े संग्रह के क्षेत्र की दूरी को भरना होगा ?

उत्तर – पहला संग्रह है दूसरा भण्डारण और प्रबंधन। हमने आंकड़े प्रबंधन के लिए दो दिन की कार्यशाला का आयोजन किया था। मेरा तात्पर्य है कि ऐसा नहीं होता कि हम हर समय जानते हैं या सभी आंकड़े इक्ट्ठे करते हैं। उदाहरण के लिए जब भूमि के बारे में प्रश्न उठता है तो हमारी एजेंसियों के पास बड़ी मात्रा में आंकड़े होते हैं। अब समय आ गया है कि मॉडल बनाने और डाटा माइनिंग के क्षेत्र में जाएँ। इस क्षेत्र में हमें कुछ विशेषज्ञ बनाने की आवश्यकता है।

प्रश्न – अब अन्तिम दो प्रश्न। भारत सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार फसल विविधिकरण की बात कर रही है। आप समझते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी फसलों की विविधता में सहायता मिलेगी जिसके लिए वैकल्पिक फसलों के न्यूनतम समर्थन में वृद्धि करनी होगी ?

उत्तर – हो सकता है किन्तु आप जानते हैं कि यदि हम केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निर्भर रहें तो यह ठीक नहीं होगा। ऐसा करने के अन्य कई तरीके भी हैं।

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2012-14
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० U(C)-92/2012-14
प्रकाशन की तिथि : 1 फरवरी, 2013
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली-2
तारीख 4 एवं 5, फरवरी 2013

कभी–कभी न्यूनतम समर्थन मूल्य की आवश्यकता होती है तो कभी दालों की बिकी महँगे दामों पर हो रही होती। कभी–कभी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता जैसे उदाहरण के लिए धान है। इस प्रकार किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एक उपयोगी औजार है। किन्तु बहुत सी विनासशील जिन्सों के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। अतः हमारा मानना है कि एक अच्छी कोल्ड़ चैन, मण्डियों से संपर्क अच्छा होने से जिन्सों का अच्छा मूल्य मिलेगा। संबंधित क्षेत्रों पर ही प्राथमिक प्रसंसाधन की सुविधा से भी अधिक मूल्य मिल सकता है जो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी अधिक हो सकता है। अन्नानास, आम जैसे विनाशशील फलों के लिए प्राथमिक प्रसंसाधन से अच्छा मूल्य प्राप्त होने के आसार हैं।

प्रश्न – अब प्रत्येक व्यक्ति प्रस्तावित दूसरी हरित कांन्ति की बात कर रहा है। हमने प्रथम हरित कान्ति से ऐसा क्या सीखा जो दूसरी हरित कान्ति में घटित न हो ?

उत्तर – कृप्या इसे मत दौहराए। सर्वप्रथम हम पहली कान्ति की बात करते हैं। हम इसी की बात कर रहे हैं। क्या यह सम्भव है कि जनसंख्या में 3–4 गुना वृद्धि होने पर भी हमने कोई कान्ति की बात नहीं कही ?

प्रश्न – आप ऐसा क्या चाहते हैं कि आप बेहतर ढंग से कार्य कर सकें ?

उत्तर – सबसे पहले हम आधुनिक आधारभूत सुविधाओं, प्रयोगशालाओं और खेती के कुँओं की बात करते हैं, जब लोग इस कार्य में आते हैं तो सर्वप्रथम इन्हीं क्षेत्रों को देखते हैं। दूसरे पद्धति में सुधार करना होगा जो बहुत सी जिंसों के लिए आवश्यक है जैसे हमारी खरीद पद्धति और कार्य करने की विधि। और भी कई चीजें हैं। हम कड़े प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सी वस्तुओं में परिवर्तन करके सफलता प्राप्त कर सकें।

प्रश्न – आपका कहने का तात्पर्य है कि राज्य स्तर पर आधारभूत सुविधाएँ होनी चाहिए ?

उत्तर – मानवक्षमता और अच्छी प्रयोगशालाओं में इनका प्रशिक्षण तथा क्षमता का नियमित निर्माण।

धन्यवाद !

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–46121708, 65650384, ई–मेलः contact@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।